



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252056
CG-DL-E-13022024-252056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945

No. 34]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2024

मामला संख्या: सीवीडी (ओआई) – 04/2023

विषय: वियतनाम में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास" के आयात से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/32/2023-डीजीटीआर.—1. मैसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित), ने सीमा शुल्क के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। समय-समय पर संशोधित टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित), वियतनाम में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए (इसके बाद 'विषय देश' के रूप में संदर्भित) टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे वह लेपित हो या बिना लेपित हो, पर सब्सिडी का आरोप लगाकर प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग की गई है।

क. सब्सिडी का आरोप

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें भी शामिल हैं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य 'सार्वजनिक निकाय'। आवेदक ने प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों में से और अन्य जांच अधिकारियों के निर्धारण में, जिन्होंने ऐसी स्कीमों की व्यापक जांच की थी और प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला था।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, वियतनाम सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 26.12.2023 को आरंभ पूर्व परामर्श आयोजित किए गए थे। वियतनामी सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को अभिलिखित कर लिया गया है और जांच के दौरान उन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबंधित देश में विषय वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को वियतनाम की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। कथित सब्सिडी में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और धन या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है, वह पहले से चला गया है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; आदि।

क. गैर-टैरिफ क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क छूट

ख. मशीनरी और उपकरणों के आयात पर आयात शुल्क में छूट

ग. कॉर्पोरेट आयकर में कमी

घ. भूमि और पानी के किराए की छूट और कमी

ङ. निवेश सहायता

च. वियतनाम विकास बैंक द्वारा निवेश ऋण

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें वियतनाम या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों से वित्तीय योगदान शामिल है, जिसमें सार्वजनिक निकाय शामिल हैं और प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करते हैं। इन योजनाओं को कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित होने का भी आरोप लगाया जाता है और इसलिए विशिष्ट और प्रतिकारी सक्षम हैं।

6. नामित प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो जांच के दौरान विषय वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मौजूद और प्राप्त किया जा सकता है।

घ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संबंध

7. आवेदक ने वियतनाम से राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विषय देश से आयात किए गए विषय की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों अर्थों में बढ़ी है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण मूल्य दमन और मंदी घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिलाभ दर प्राप्त करने के लिए अपने मूल्यों में वृद्धि करने से रोकती रही है। आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता पैरामीटरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण क्षति जांच अवधि के

दौरान नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई ऋणात्मक होते हैं। घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया वियतनाम से कथित राज सहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाते हैं।

ड. जाँच की शुरूआत

8. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करके, जिसमें पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि की गई है, प्राधिकरण एतद्वारा नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ख के अनुसार घरेलू उद्योग को कथित पाटन और परिणामी सामग्री क्षति की सब्सिडी-रोधी जांच शुरू करता है। सरकार ने कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटन शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक अधिनियम गठित किया है जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

च. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“घरेलू उद्योग” से ऐसी संपूर्ण वस्तु के रूप में घरेलू उत्पादक या घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं, जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी वाली वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों, या स्वयं उसके आयातक हों, जिस मामले में ऐसे उत्पादकों को “घरेलू उद्योग” का हिस्सा नहीं माना जाएगा

10. आवेदन मेसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन के अनुसार भारत में एक और निर्माता है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान आवेदक से अलग मेसर्स गोबिंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हालाँकि, आवेदन दाखिल करने के बाद, प्राधिकरण को चार और घरेलू उत्पादकों अर्थात् मेसर्स त्रिवेणी ग्लास, मेसर्स विशाखा रिन्यूएबल्स, मेसर्स इमर्ज ग्लास और मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास लिमिटेड से समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू किया। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के दौरान आवेदक के अलावा पीयूसी के पांच और उत्पादक हैं और भारत में कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आवेदक का है।
11. आवेदक ने विषय देश से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा आवेदक पीओआई के दौरान विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।
12. जांच दल की राय है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीवीडी नियम, 1995 के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन सीवीडी नियम, 1995 के नियम 6 (3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

छ. विचाराधीन उत्पाद

13. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "टेक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई कम से कम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड" (इसके बाद "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास" या "टीटीजी" या "विषय सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी जाना जाता है। उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे कि सौर ग्लास, कम लोहा सौर ग्लास, सौर ग्लास कम लोहा, सौर फोटोवोल्टिक ग्लास, उच्च संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड कम लोहे पैटर्न वाले सौर ग्लास, आदि।
14. बनावट टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। लोहे की सामग्री को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200

पीपीएम से कम। एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ लेपित होने पर संचरण स्तर लगभग 2% -3% बढ़ जाता है।

15. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के परिचालित होने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन), यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुच्छेद 24 में दर्शाया गया है।

ज. समान वस्तु

16. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात किए गए वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और वियतनाम से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा निर्मित विषय वस्तुएं और उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए जांच दलयह धारण करने का प्रस्ताव करता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु वियतनाम से आयात किए जा रहे उत्पाद समान है।

झ. शामिल देश

17. आवेदन वियतनाम में उत्पन्न होने वाले या उससे निर्यात किए जाने वाले विषय माल के कथित सब्सिडी के संबंध में दायर किया गया है। इस लिए वर्तमान जांच के लिए विषय देश वियतनाम है।

ब. जांच की अवधि

18. आवेदक ने 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 (12 महीने) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है (इसके बाद इसे 'पीओआई' भी कहा गया है)। हालांकि, प्राधिकरण ने पीओआई को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) माना है। क्षति की जानकारी पीओआई और तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रदान की गई है, यानी 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना,

नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य इच्छुक पार्टी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों, और इस शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक प्रस्तुतिकरण भी कर सकती है।

22. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (<https://www.dgtr.gov.in/>) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर और एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए उस तारीख से 30 दिनों के भीतर जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या सीवीडी नियमों के नियम 7(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

25. सभी इच्छुक पक्षों को यहां सूचित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने हितों (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और अपनी प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

26. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती है, उसे सीवीडी नियम, 1995 के नियम 7 (4) के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना चाहिए और इस तरह का अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्ष को सीवीडी नियमों के नियम 8 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

28. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकरण को की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से गोपनीय है और / या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

31. गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश अपर्याप्त विवरण होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों, 1995 के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण और जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस प्राधिकरण द्वारा, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

32. इच्छुक पार्टियां इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के अनुच्छेद 24 में दर्शाए अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर इच्छुक पार्टियां द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।
33. गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण कथन के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतिकरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
35. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।
36. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता से इस जाँच शुरुआत अधिसूचना की धारा 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

ढ. असहयोग

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष उचित अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा इस आरंभिक अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर या बाद में अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकरण घोषणा कर सकता है ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी मानेगा और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करेगा और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जो वह उचित समझे।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2024

Case No. CVD (OI) – 04/2023

Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Textured Tempered Coated and Uncoated Glass” originating in or exported from Vietnam.

F. No. 6/32/2023-DGTR.—1.M/s Borosil Renewables Limited, (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of countervailing duty investigation by alleging subsidization of textured tempered glass whether coated or uncoated”, originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

A. Allegation of subsidization

2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the government of the subject country, including the government of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other public bodies. The applicant has relied upon the relevant laws, rules, regulations and other notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in

the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 26.12.2023 with the representatives of the Government of Vietnam. The comments received from the Vietnamese government have been taken on record and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

C. Subsidy programs

4. The *prima facie* evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the government of Vietnam and/or their respective public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.
- a. Import duty exemption on imports of raw materials for enterprises in non-tariff zones
 - b. Import duty exemption on imports of machinery and equipment
 - c. Reduction of corporate income tax
 - d. Exemption and reduction of land & water rent
 - e. Investment support
 - f. Investment credit by Vietnam Development Bank
5. It has been alleged that the above-mentioned schemes are subsidies since these involve a financial contribution from the government of Vietnam or other regional or local, including public bodies and confer a benefit on the recipient(s). These schemes are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable.
6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

D. Allegation of injury and causal Link

7. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the subsidized imports from Vietnam. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilization of the domestic industry has declined. The price suppression and depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of return. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT and ROCE are negative throughout the injury investigation period. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicant *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidized imports from Vietnam.

E. Initiation of the investigation

8. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the subsidization and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-subsidy investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry & Standing

9. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”

10. The application has been filed by M/s Borosil Renewables Limited. As per the application there is one more producer in India, viz. M/s Gobind Glass & Industries Ltd. apart from the applicant during the POI proposed by the applicant. However, post filing of the application, the Authority has received support letters from four more domestic producers namely M/s Triveni Glass, M/s Vishakha Renewables, M/s Emerge Glass and M/s Gold Plus Glass Ltd., who have recently commenced the production of the product under consideration. Hence, during the POI adopted by the Authority there are five more producers of the PUC apart from the applicant and the applicant still accounts for a major proportion of the total production in India.
11. The applicant has not imported the subject goods from the subject country. The applicant is also not related to any the importer or the exporter of the subject goods.
12. Since the production of the applicant accounts for a major proportion of the total production of the subject goods in India, the applicant satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 6(3) of the CVD Rules, 1995.

G. Product under consideration

13. The product under consideration in the present application is “textured toughened (tempered) glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated” (hereinafter also referred to as “textured tempered glass” or “TTG” or “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”). The product is also known by various names such as solar glass, low iron solar glass, solar glass low iron, solar photovoltaic glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass, etc. in the market parlance.
14. Textured tempered glass is used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.
15. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose product control numbers (PCNs), if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority as indicated in paragraph 24 of this initiation notification.

H. Like Article

16. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and imported from Vietnam are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as like article to the product being imported from Vietnam.

I. Country involved

17. The application has been filed in respect of alleged subsidization of the subject goods originating in or exported from Vietnam. Therefore, the subject country for the present investigation is Vietnam.

J. Period of Investigation

18. The applicant has proposed 1stJuly 2022 to 30th June 2023 (12 months) as the period of investigation (hereinafter also referred to as ‘POI’). However, the Authority has considered the POI as 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The injury information has been provided for the POI and three preceding years, i.e., April 1, 2020 to March 31, 2021, April 1, 2021 to March 31, 2022, April 1, 2022, to March 31, 2023.

K. Submission of Information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits

mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
26. Where an interested party seeks addition al time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of information on confidential basis

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as non-confidential information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any interested party within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 24 of this initiation notification.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to action under Section N of this initiation notification.

N. Non-Cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority